Journal Homepage: www.ijrpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 02, Issue 06, pp 179-188, June 2025

नक्सलवाद पर चोट करते ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और कुर्रेगुट्टालू अभियान का विश्लेषण

पुखराज प्राज

*सहायक प्राध्यापक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, SDU, **नया रायपुर***

Email Id : praajsir@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.55248/gengpi.6.0625.2221

सार :

अप्रैल–मई 2025 में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चलाए गए कुर्रेगुट्टालू अभियान और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भारत की नक्सलवाद विरोधी लड़ाई के सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुए। इन अभियानों में सुरक्षा बलों ने माओवादी संगठनों को भारी क्षति पहुँचाई और उनके शीर्ष नेतृत्व को समाप्त कर दिया। कुर्रेगुट्टालू अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने 21 दिनों तक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर 31 माओवादियों को मार गिराया, जिनमें 16 महिला नक्सली शामिल थीं। इसके अलावा, 214 नक्सली बंकर नष्ट किए गए और सैकड़ों विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इस अभियान से PLGA बटालियन, सेंट्रल रीजनल कमांड (CRC) और तेलंगाना स्टेट कमेटी जैसे संगठनों की कमर टूट गई। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और सुरक्षा बलों ने स्थायी कैंप स्थापित कर आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इसके कुछ सप्ताह बाद, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अंजाम दिया गया, जिसमें 27 खूंखार माओवादी मारे गए। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी सफलता रही CPI (Maoist) के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बासवराजू का मारा जाना। यह पहली बार था जब भारत की नक्सल विरोधी लड़ाई में शीर्ष स्तर के नेता को समाप्त किया गया। बासवराजू माओवादी आंदोलन की रणनीति और संचालन का केंद्रीय चेहरा था, और उसकी मृत्यु से संगठन की विचारधारा और नेतृत्व दोनों को गहरा झटका लगा। इन दोनों अभियानों के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियों में तेजी आई है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, कई माओवादी नेताओं ने भूमिगत जीवन छोड़ने के संकेत दिए हैं। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये अभियान न केवल सैन्य दृष्टिकोण से सफल रहे, बल्कि उन्होंने यह संदेश भी दिया कि भारत अब नक्सलवाद के समूल नाश की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ चुका है। यह अनुमान अब और मजबूत हो गया है कि 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है।

कूटशब्द: ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, कुर्रेगुट्टालू अभियान (KGH Operation), नक्सलवाद, माओवादी आंदोलन, PLGA बटालियन , CPI (Maoist), छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा, सुरक्षाबल , विस्फोटक सामग्री, बंकर, मुठभेड़ , आत्मसमर्पण , नक्सल मुक्त भारत, गृह मंत्रालय ।

नक्सलवाद क्या है?

नक्सलवाद (Naxalism) एक उग्र वामपंथी आंदोलन है, जिसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई थी। यह आंदोलन मुख्यतःसामाजिक और आर्थिक असमानताओं के विरुद्ध था। नक्सली विचारधारा माओवादी विचारों से प्रेरित होती है, जिसमें सशस्त्र संघर्ष के ज़रिए सरकार को चुनौती देने की बात की जाती है। इसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों, आदिवासियों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन समय के साथ यह आंदोलन हिंसात्मक गतिविधियों में बदल गया। नक्सलवाद को समझने के लिए केवल उसकी हिंसात्मक प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों को भी विश्लेषित करना आवश्यक है। बिपिन चंद्रा के अनुसार, नक्सलवाद मूलतः ग़रीबी, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ एक सामाजिक-आर्थिक विद्रोह के रूप में उभरा, जो बाद में हिंसा में बदल गया।[1] इस आंदोलन ने भारत के ग्रामीण और हाशिए पर खड़े वर्गों की गहरी असंतोष की भावना को स्वर दिया, जैसा कि वाल्टर हॉज़र ने भी उल्लेख किया कि यह आंदोलन ग्रामीण भारत की आर्थिक असमानता के प्रति असंतोष का परिणाम है, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी मार्ग को अपनाता है।[2] सुमंत बनर्जी नक्सलवाद को एक 'अल्टरनेटिव रिवोल्यूशनरी मॉडल' मानते हैं, जो किसानों और आदिवासियों को सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए उग्र रास्ता अपनाता है।[3] यह दृष्टिकोण आंदोलन की उस वैचारिक पृष्ठभूमि को उजागर करता है, जिसमें सत्ता की पारंपरिक संरचनाओं को चुनौती देने की चेष्टा है। वहीं, नंदिनी सुंदर नक्सलवाद को राज्य और समाज के टूटे हुए रिश्तों का परिणाम मानती हैं, जिसमें राज्य की नीतिगत विफलताएँ और हाशिए पर पड़े समुदायों की उपेक्षा प्रमुख भूमिका निभाती हैं।[4] इससे यह स्पष्ट होता है कि आंदोलन की

जड़ें केवल आर्थिक विषमता में नहीं, बल्कि राजनीतिक बहिष्कार और सामाजिक उपेक्षा में भी हैं। अंततः जैसा कि रामचंद्र गुहा कहते हैं, नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है, क्योंकि यह राज्य की वैधता और अधिकार को सीधी चुनौती देता है।[5] इन विद्वानों के विश्लेषणों को समग्र रूप से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि नक्सलवाद एक बहुआयामी संकट है— जिसमें सामाजिक अन्याय, राज्य की विफलताएँ, और हिंसात्मक विचारधारा एक साथ मिलकर एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करते हैं।

नक्सलवाद की उत्पत्ति: एक ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य :

भारत में नक्सलवाद का जन्म 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में एक किसान विद्रोह के रूप में हुआ था। यह विद्रोह भूमि के पुनर्वितरण और स्थानीय जमींदारों के शोषण से मुक्ति की मांग को लेकर शुरू हुआ था[6] । हालांकि यह आंदोलन स्थानीय प्रतीत होता था, लेकिन इसने भारत की गहराई से जमीं हुई सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर किया। स्वतंत्रता के बाद भी औपनिवेशिक काल की भूमि-स्वामित्व प्रणालियाँ बनी रहीं। 1971 की जनगणना के अनुसार, लगभग 60% भारतीय आबादी भूमिहीन थी जबकि केवल 4% लोगों के पास अधिकांश कृषि भूमि थी।[7] यह विषमता ग्रामीण समाज में विद्रोह की नींव बन गई। नक्सलवाद केवल एक सामाजिक असंतोष नहीं था, बल्कि यह भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के वैचारिक संघर्षों का भी परिणाम था। 1925 में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का मूल उद्देश्य मजदूर वर्ग के नेतृत्व में क्रांति था। परंतु 1950 के दशक में सोवियत संघ के प्रभाव में आकर पार्टी ने सशस्त्र संघर्ष छोड़कर संसदीय लोकतंत्र को अपनाने का निर्णय लिया ।[8] इस परिवर्तन से पार्टी के भीतर एक कट्टरपंथी गुट असंतुष्ट हो गया, जिससे 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] का जन्म हुआ। हालांकि CPI(M) भी जब 1967 में चुनावों में भाग लेने लगी और सत्ता में आई, तब चारु मजूमदार जैसे नेताओं ने इसे 'सुधारवादी' मानते हुए एक नई क्रांतिकारी राह अपनाई ।[9] मजूमदार ने माओत्से तुंग की रणनीति को अपनाते हुए गांवों से जन युद्ध शुरू करने की योजना बनाई और 1969 में CPI (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [CPI(ML)] की स्थापना की ।[10] मजूमदार का नारा – "चीनी चेयरमैन हमारा चेयरमैन है" – माओवादी विचारधारा के प्रति गहन प्रतिबद्धता का परिचायक था। परंतु मजूमदार की रणनीति व्यावहारिक नहीं थी और 1971 में 'ऑपरेशन स्टीपलचेज़' के तहत सरकार ने नक्सलवाद की पहली लहर को लगभग समाप्त कर दिया[11]। लेकिन आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण और खनन परियोजनाओं के कारण आदिवासी समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। इससे एक बार फिर असंतोष भड़का, जिसे नक्सलवादी संगठनों ने अपनी विचारधारा के प्रचार और विस्तार के लिए प्रयोग किया। 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय से CPI (माओवादी) का गठन हुआ, जो आज भी देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर 'रेड कॉरिडोर' में सक्रिय है।[12] भारत सरकार ने CPI (माओवादी) को 2009 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत प्रतिबंधित किया और सुरक्षा बलों के माध्यम से ठोस अभियान चलाए। इसके साथ ही सरकार ने विकास योजनाएं भी लागू कीं, लेकिन नक्सलवाद की जड़ में छिपी सामाजिक-आर्थिक असमानता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।[13] रामचंद्र गुहा के अनुसार, नक्सलवाद केवल एक हिंसक आंदोलन नहीं है, बल्कि यह राज्य और समाज के बीच टूटे हुए संबंधों का प्रतीक है।[14] यह उन लाखों लोगों की आवाज है जो विकास की मुख्यधारा से बाहर हैं और जिनके लिए लोकतंत्र अब भी एक अधूरी परिकल्पना है। नक्सलवाद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है – जब तक समानता, न्याय और समावेशी विकास सुनिश्चित नहीं होते, तब तक इस तरह के आंदोलनों का पुनरुत्थान होता रहेगा। यह आंदोलन भले ही समय-समय पर रूप बदलता रहा हो, लेकिन इसकी जड़ें भारत की संरचनात्मक असमानताओं और सामाजिक उपेक्षा में ही रही हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा की शुरुआत :

छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा का उदय कोई अचानक या अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि दशकों की संरचनात्मक उपेक्षा, प्रणालीगत अन्याय और सामाजिक-राजनीतिक बहिष्कार का परिणाम है। यह समझने के लिए कि इस राज्य में इस विद्रोह ने इतनी गहरी जड़ें क्यों जमा लीं - खासकर बस्तर क्षेत्र में - सतह से परे देखना और ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों की जांच करना आवश्यक है, जिसने छत्तीसगढ़ को वामपंथी उग्रवाद के लिए उपजाऊ जमीन बना दिया। भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में हुई थी, जहां भूमिहीन किसानों ने दमनकारी जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसने माओवादी विचारधारा से प्रेरित एक कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें कृषि क्रांति हासिल करने के लिए सशस्त्र संघर्ष पर जोर दिया गया। समय के साथ, यह आंदोलन भारत के सबसे हाशिए पर और वन क्षेत्रों में फैल गया, जिसे अक्सर "लाल गलियारा" कहा जाता है, जिसमें झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी (आदिवासी) समुदाय रहते हैं, विशेष रूप से असुरक्षित था। ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा के विकास की प्रक्रिया से अलग-थलग रहने के कारण, इन समुदायों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा: खनन के कारण भूमि का नुकसान, वन अधिकारों से वंचित होना, और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार तक पहुँच की कमी। इन आंतरिक क्षेत्रों में राज्य की उपस्थिति न्यूनतम थी, और जो भी उपस्थिति थी, उसे अक्सर सहायक के बजाय बलपूर्वक माना जाता था। बनर्जी के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों ने क्रांतिकारी आंदोलन को जड़ जमाने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान कीं, क्योंकि राज्य की उपेक्षा और कॉर्पोरेट शोषण ने सभी संस्थागत विश्वास को खत्म कर दिया था।[15]

जब छत्तीसगढ़ 2000 में एक अलग राज्य बना, तो विकास और स्थानीय शासन की उम्मीदें अधिक थीं। हालाँकि, समावेशी विकास के बजाय, नए राज्य ने औद्योगीकरण और खनिज निष्कर्षण को प्राथमिकता दी। इससे और अधिक आदिवासी विस्थापन हुआ और स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी पैदा हुई। पर्याप्त मुआवजे या पुनर्वास के बिना खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण ने समुदायों को और अलग-थलग कर दिया, जिससे वे नक्सली कथाओं के प्रति ग्रहणशील हो गए, जो खुद को आदिवासी अधिकारों और न्याय के रक्षक के रूप में स्थापित करते हैं ।[16] 2005 में राज्य समर्थित निगरानी आंदोलन 'सलवा जुडूम' के गठन के साथ स्थिति काफी बिगड़ गई। हालाँकि इसे आदिवासी युवाओं को संगठित करके और स्थानीय प्रतिरोध पैदा करके नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन यह एक विवादास्पद और हिंसक अभियान बन गया। ह्यूमन राइट्स वॉच सहित कई मानवाधिकार संगठनों ने जबरन बेदखली, गाँवों को जलाने, मनमानी गिरफ़्तारियाँ और बाल सैनिकों की भर्ती का दस्तावेजीकरण किया।[17] विद्रोह को दबाने के बजाय, सलवा जुडूम ने संघर्ष को एक आभासी गृहयुद्ध में बदल दिया, जिससे हज़ारों लोग विस्थापित हो गए और कई लोग जीवित रहने और सुरक्षा के लिए नक्सलियों के हाथों में चले गए।

इस प्रकार 2000 के दशक की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में एक पूर्ण विकसित संघर्ष का क्रिस्टलीकरण हुआ। शासन की विफलता - विशेष रूप से बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने, आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में - ने एक शून्य पैदा किया जिसे नक्सलियों ने भर दिया। उन्होंने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में न्याय, शिक्षा और स्थानीय शासन की समानांतर व्यवस्थाएँ बनाईं। हालांकि ये व्यवस्थाएं अक्सर क्रूर और सत्तावादी होती हैं, लेकिन कई स्थानीय लोगों ने इन्हें राज्य संस्थाओं की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील माना [18] । आज, छत्तीसगढ़ खुद को एक ऐसे राज्य के बीच फंसा हुआ पाता है जो अक्सर बल प्रयोग करता है और एक नक्सली आंदोलन जो शिकायतों और मोहभंग पर पनपता है। हालांकि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और कुर्रेगुट्टालू जैसे हालिया अभियानों ने नक्सल नेतृत्व को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, लेकिन विचारधारा जीवित है क्योंकि मूल कारण बने हुए हैं- भूमि अलगाव, गरीबी, प्रशासनिक उदासीनता और आदिवासियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। जैसा कि गुहा तर्क देते हैं, नक्सलवाद केवल सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है बल्कि एक गहरा नैतिक और राजनीतिक संकट है।[19] इस आंदोलन को जन्म देने वाली संरचनात्मक असमानताओं और ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित किए बिना, कोई भी सैन्य रणनीति स्थायी शांति नहीं लाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा की शुरुआत केवल एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी भी है। यह उस समाज की करुण पुकार है, जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है। अगर हम इस पुकार को आज नहीं सुनते, तो कल यह और अधिक हिंसक और भयावह रूप ले सकती है। अब समय आ गया है कि हम केवल परिणामों से नहीं, बल्कि कारणों से लड़ें – और यही छत्तीसगढ़ को एक शांतिपूर्ण भविष्य की ओर ले जा सकता है।

2013 से 2023 तक नक्सली हिंसा पर आधारित रिपोर्ट :

वर्ष	नक्सली हमले	शहीद जवान	मारे गए नक्सली
2013	355	44	38
2014	328	60	35
2015	466	48	48
2016	395	38	135
2017	373	60	80
2018	392	55	125
2019	263	22	79
2020	315	36	44
2021	255	45	48

वर्ष	नक्सली हमले	शहीद जवान	मारे गए नक्सली
2022	**305**	**10**	**31**
2023	**41**	**7**	**1**

(स्रोत: आजतक न्यूज़ आधिकारिक पेज)

भारत सरकार और सुरक्षाबलों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के चलते देश में नक्सली गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2015 और 2016 में नक्सली हमलों और सुरक्षा बलों के शहीद जवानों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उस समय नक्सलवाद अपने चरम पर था। विशेष रूप से 2016 में 135 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिली, जो यह दर्शाता है कि उस वर्ष सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ तीव्र और आक्रामक जवाबी अभियान चलाए थे। इसके बाद के वर्षों में सरकार ने जहां एक ओर सुरक्षा अभियानों को सुदृढ़ किया, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों, आधारभूत ढांचे के विस्तार और आदिवासी क्षेत्रों में विश्वास बहाली की दिशा में भी प्रयास किए। इन समग्र प्रयासों का प्रभाव 2019 के बाद दिखाई देने लगा, जब नक्सली हमलों में लगातार कमी दर्ज की गई। 2022 और 2023 में तो नक्सली घटनाएं अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गईं। विशेष रूप से 2023 में केवल 41 नक्सली हमले हुए, जिनमें 7 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए और मात्र 1 नक्सली मारा गया—जो अब तक की सबसे कम संख्या मानी जा रही है। यह न केवल सुरक्षात्मक सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि सरकार की बहु-आयामी रणनीति, जिसमें सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक सुधारों को जोड़ा गया है, नक्सलवाद पर अंकुश लगाने में प्रभावी सिद्ध हो रही है।

कुर्रेगुट्टालू अभियान का गूढ़ विश्लेषण :

वर्ष 2025, 21 अप्रैल से 11 मई तक भारत सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित कुर्रेगुट्टालू पहाड़ी क्षेत्र में चलाया गया 21 दिवसीय समन्वित सैन्य अभियान, नक्सलवाद के विरुद्ध एक उल्लेखनीय सफलता के रूप में सामने आया। यह क्षेत्र दशकों से नक्सलियों का मजबूत गढ़ रहा है, जहाँ PLGA बटालियन-1, तेलंगाना राज्य समिति, दंडकारण्य विशेष अंचल समिति और केंद्रीय क्षेत्रीय समिति जैसे प्रमुख संगठन सक्रिय थे। इस अभियान में केंद्रीय सुरक्षा बलों, छत्तीसगढ़ पुलिस, विशेष कार्य बल , जिला रिजर्व गार्ड और अन्य एजेंसियों ने मिलकर रणनीतिक एवं पेशेवर ढंग से कार्य किया। इस दौरान कुल 31 नक्सली मारे गए, जिनमें 16 महिलाएं थीं। इनमें से कई पर कुल मिलाकर 1.72 करोड़ रुपये तक का इनाम घोषित था। सबसे विशेष बात यह रही कि इतने बड़े अभियान में किसी भी जवान की जान नहीं गई, जो इस रणनीति की संतुलित और सफल योजना को दर्शाता है।कुर्रेगुट्टालू क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना – घने जंगल, गुफाएं, आईईडी जाल और घातक हमलों के स्थान – इसे एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और रणनीतिक स्थल बनाते हैं। नक्सलियों ने इसे एक स्थायी अड्डा बना रखा था, जहाँ हथियार निर्माण इकाइयां, तकनीकी विभाग और राशन व चिकित्सा सामग्री का भंडारण होता था। अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने 214 बंकर, 4 हथियार निर्माण इकाइयां, और 12,000 किलोग्राम से अधिक राशन सामग्री बरामद की। साथ ही 450 आईईडी, 818 बीजीएल शेल, 899 कोडेक्स बंडल और अनेक डेटोनेटर ज़ब्त किए गए, जो नक्सलियों की हिंसक मंशा को उजागर करते हैं। 45 डिग्री तापमान जैसी भीषण गर्मी में भी जवानों ने अद्वितीय साहस, संयम और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। इसका उद्देश्य केवल नक्सलियों को समाप्त करना नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र को तोड़ना था जो वर्षों से हिंसा, डर और विकासहीनता का प्रतीक बना हुआ था। सरकार अब इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना के ज़रिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्यरत है। गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 2026 , 31 मार्च तक देश को पूर्णतः नक्सलमुक्त बनाने का लक्ष्य अब अधिक साकार प्रतीत होता है। यदि सरकार इसी दृढ़ता और समर्पण के साथ आगे बढ़ती रही, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत एक सुरक्षित, समृद्ध और न्यायपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। कुर्रेगुट्टालू अभियान केवल एक सैन्य सफलता नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की संकल्पबद्ध और दूरदर्शी नीति का प्रतीक है, जो हर नागरिक के लिए सुरक्षा, सम्मान और समानता से परिपूर्ण समाज की स्थापना की दिशा में अग्रसर है।[20]

मापदंड	2014	2024/2025
अत्यधिक नक्सल प्रभावित ज़िले	35	6
कुल नक्सल प्रभावित ज़िले	126	18
नक्सली घटनाएं	1080	374
घटना वाले ज़िले/थाने	76 ज़िले / 330 थाने	42 ज़िले / 151 थाने
शहीद सुरक्षाकर्मी	88	19
मुठभेड़ में मारे गए नक्सली	63	2089
सरेंडर करने वाले नक्सली	-	2024: 928 2025 (जन–अप्रैल): 718
स्थापित सुरक्षा कैंप (2019–2025)	-	320
↳ नाइट लैंडिंग हैलीपैड	-	68
फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन	66	555
2025 के पहले 4 माह में न्यूट्रलाइज़ नक्सली	-	197

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता :

वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भारत की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक रहा। इस अभियान में 27 माओवादी मारे गए, जिनमें CPI (माओवादी) के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बासवराजू प्रमुख था। बासवराजू की मृत्यु ने नक्सली संगठन की शीर्ष नेतृत्व संरचना को गंभीर क्षति पहुंचाई और PLGA जैसे सशस्त्र संगठनों की ताकत को कमजोर किया। ऑपरेशन के बाद 54 नक्सली गिरफ्तार हुए और 84 ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें कई इनामी कैडर थे। यह नक्सलियों में बढ़ते भय और हतोत्साह का संकेत है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई त्रिस्तरीय रणनीति – सुरक्षा वर्चस्व, विकास का प्रसार और पुनर्वास – इस अभियान की सफलता में निर्णायक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में "Whole-of-Government Approach" को लागू करते हुए सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और प्रशासन के समन्वित प्रयासों से यह संभव हो सका। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अब भी नक्सलियों का सीमित प्रभाव शेष है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के पतन और आत्मसमर्पण की बढ़ती दर यह स्पष्ट करती है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और कुर्रेगुट्टालू अभियान जैसे समन्वित प्रयास यह संकेत हैं कि भारत अब नक्सलवाद को केवल सैन्य नहीं, बल्कि वैचारिक और सामाजिक स्तर पर भी शिकस्त देने की स्थिति में आ चुका है। यदि यही गति बनी रही, तो 31 मार्च 2026 से पहले "नक्सलमुक्त भारत" का सपना न केवल पूरा होगा, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक विजय की एक गौरवपूर्ण गाथा होगी।[21]

TIMES CITY

Another top Maoist with ₹45L bounty killed in encounter

Preliminary Identification Indicates It's Bhaskar: Bastar IG

Rashmi.Drolia
@timesofindia.com

Raipur: In yet another big blow to the Left Wing Extremism (LWE), another senior Maoist rank cadre — Bhaskar, who carried Rs 45 lakh bounty — was neutralized on Friday in an encounter that broke out in the same area where Maoists central committee member Sudhakar alias Tentu Lakshmi Narasimha Chalam was gunned down on Thursday in the forests of Bijapur.

The encounter was part of the same anti-Maoist operation underway since Wednesday being carried out by personnel from the state police's Special Task Force (STF), District Reserve Guard (DRG) and CoBRA.

Intermittent firing between security forces and the Maoist ultras took place the whole day and after the guns fell silent, security forces recovered the body of 45-year-old Maoist **Bhaskar**, who carried a bounty of Rs 25 lakh in Chhattisgarh and Rs 20 lakh in Telangana.

Bhaskar was a Special Zonal Committee member of Telangana State Committee and was reportedly operating in the dense forests of Indravati National Park — a known Maoist stronghold.

Three days ago, **TOI** had reported that security forces in Bastar have precise information on the locations of nine top Maoist commanders in Bastar division, and an operation to eliminate them is imminent unless they surrender.

Speaking to **TOI**, Bastar range inspector general of police P Sundarraj said, "As part of the ongoing anti-Naxal operation in the National Park area of Bijapur district, security forces have recovered the dead body of another male cadre. Preliminary identification indicates that the recovered body is that of Bhaskar alias Mailarapu Adellu, a member of the Telangana State Committee."

IG stated that an AK-47 rifle along with other explosives, weapons, and ammunition have been recovered from the encounter site.

"Bhaskar, a resident of Adilabad district in Telangana, was the Secretary of the Mancherial-Komarambheem (MKB) division of the CPI (Maoist) outfit," the IG further said.

In the same operation on June 5, security forces had recovered the body of Central Committee member Gautam alias Sudhakar along with an AK-47 rifle.

The search operation in the area is still ongoing to trace other Maoist cadres in the nearby area.

Detailed information regarding other Maoist casualties and recoveries will be shared after the operation concludes and full confirmation is received.

Naxals torch truck in frustration after killing of sr leader: Cops

Raipur: Naxalites on Thursday torched a truck in Chhattisgah's Bijapur district, where a senior Maoist leader was killed in an encounter with security forces earlier in the day, police said.

The incident occurred at around 9 pm between Karremarka and Bhairamgarh in the district, a police statement said, quoting eyewitnesses.

Around half a dozen Naxalites dressed as civilians stopped the truck on a national highway and asked its occupants to alight. They then poured petrol on the vehicle, belonging to a private transporter, and set it ablaze, police said.

However, movement of traffic on the road remained unaffected, said the statement.

Maoists committed the arson in frustration after the killing of their central committee member Sudhakar in an encounter with security forces, the statement said.

Police personnel were rushed to the spot and combing operations to apprehend the Naxalites were launched, he added.

Senior Maoist leader Narasimha Chalam alias Sudhakar, who had a bounty of Rs 40 lakh on his head in Chhattisgarh, was killed in an encounter with security forces in the forest of Indravati national park in Bijapur on Thursday.

The killing of Sudhakar, a member of the Maoists' Central Committee, comes a fortnight after CPI (Maoist) general secretary Nambala Keshav Rao alias Basavaraju (70) was neutralised by security forces in the Bastar region, dealing a severe blow to the banned outfit. PTI

नक्सलवाद से युवाओं के जुड़ने का कारण :

नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे जटिल चुनौतियों में से एक रहा है। यद्यपि इसे राज्य के विरुद्ध हिंसक आंदोलन के रूप में देखा जाता है, इसकी जड़ें गहरी सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक असमानताओं में हैं। यह आंदोलन खासतौर पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पनपा है, जहाँ वर्षों से विकास, शिक्षा और न्याय की भारी कमी रही है। नक्सलवाद से प्रभावित भारत के अधिकतर क्षेत्र अत्यंत पिछड़े और संसाधनविहीन हैं, जहाँ बेरोज़गारी, कृषि संकट और भूख जैसी समस्याएँ आम हैं। इन इलाकों में राज्य की योजनाएँ अक्सर प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पातीं, जिससे युवाओं में असंतोष जन्म लेता है और वे विद्रोह को विकल्प मानने लगते हैं ।[22] वन अधिकारों की उपेक्षा और खनिज संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने लाखों आदिवासियों को उनके पारंपरिक निवास स्थलों से बेदखल कर दिया है, जिससे सामाजिक असंतुलन गहराया है और इसी असंतोष को नक्सली अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं।[23] भूमि सुधारों की विफलता ने इस असंतोष को और अधिक स्थायी बना दिया है। इन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहद निम्न है, जिससे युवा वैकल्पिक विचारधाराओं, विशेषकर माओवादी दर्शन की ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। जब सरकारी तंत्र युवाओं को शिक्षित करने में असफल रहता है, तब नक्सली अपने "जनता विद्यालय" और विचारधारा के ज़रिए उनके मानस को प्रभावित करते हैं ।[24] इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में अक्सर सरकार का एकमात्र चेहरा पुलिस या अर्धसैनिक बल होते हैं, जो कभी-कभी निर्दोषों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं। इससे शासन और जनता के बीच की खाई और गहरी हो जाती है। जहाँ सरकार की कल्याणकारी सेवाएँ नहीं पहुँचतीं, वहाँ नक्सली "जन अदालतों" और "समांतर शासन" के ज़रिए जनविश्वास अर्जित करते हैं ।[25]

आदिवासी और दलित समुदायों की सांस्कृतिक अस्मिता की उपेक्षा ने भी विद्रोह को बढ़ावा दिया है। जब उनके रीति-रिवाज, भाषा और जीवनशैली को मुख्यधारा में समाहित करने का दबाव डाला जाता है, तो वे असहज महसूस करते हैं और प्रतिरोध के रास्ते को अपनाते हैं।[26] नक्सली इन्हीं मुद्दों को राजनीतिक मंच पर उठाकर स्थानीय समर्थन अर्जित करते हैं। वहीं, इन क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व या तो कमजोर रहा है या बाहरी शक्तियों के नियंत्रण में रहा है, जिससे लोकतंत्र के प्रति लोगों में विश्वास नहीं बन पाया। लोग मानने लगे हैं कि चुनाव महज़ एक प्रक्रिया है, लेकिन इससे उनकी जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता।[27]

इसके साथ ही न्यायिक व्यवस्था की धीमी और खर्चीली प्रकृति ने आदिवासियों और गरीब तबकों को न्याय से वंचित कर दिया है। जब पुलिस और अदालतें उनकी शिकायतों का समाधान नहीं कर पातीं, तब वे नक्सलियों की "जन अदालतों" को ही न्याय का माध्यम मानने लगते हैं ।[28] कुछ युवाओं के लिए माओवादी विचारधारा एक आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत करती है, जिसमें शोषण रहित व्यवस्था हो। जब वे अपने समाज में गहरी असमानता और अन्याय देखते हैं, तो यह आदर्शवाद उन्हें क्रांतिकारी मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है।[29]

पारंपरिक ग्राम पंचायतों और आदिवासी सभाओं को यदि हाशिए पर डाल दिया जाता है और उनका सशक्तिकरण नहीं किया जाता, तो स्थानीय नेतृत्व कमजोर पड़ता है। इस शून्य में नक्सली कमांडर जैसे वैकल्पिक नेतृत्व सामने आते हैं, जो लोगों को संगठित करते हैं।[30] अंततः खनिज, जंगल और जल जैसे संसाधनों पर बाहरी कंपनियों के नियंत्रण से आदिवासी समुदाय का पारंपरिक जीवन संकट में पड़ गया है। यह संघर्ष अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है।[31] यह पूरा परिदृश्य दर्शाता है कि नक्सलवाद केवल एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकट का परिणाम है, जिसे केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समग्र विकास और न्याय आधारित नीति से ही हल किया जा सकता है। नक्सलवाद केवल सुरक्षा की नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, विकास और विश्वास की लड़ाई है। जब तक शासन की मुख्यधारा इन वंचित वर्गों को समान रूप से शामिल नहीं करती, तब तक ऐसी विचारधाराएं पनपती रहेंगी। एक प्रभावी रणनीति वही होगी जो सशस्त्र कार्रवाई के साथ-साथ न्याय, शिक्षा, रोजगार और संवाद पर केंद्रित हो।

नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में गिरावट (2009–2025):

वर्ष	अत्यधिक प्रभावित जिले	कुल प्रभावित जिले
2009	35	96
2015	30	82
2020	25	70
2024	10	45
2025 (अब)	**8 (अनुमानित)**	**30 (अनुमानित)**

→ *स्रोतः गृह मंत्रालय रिपोर्ट, 2025*

नक्सलवाद का अंत :

नक्सलवाद ने दशकों तक भारत के कई हिस्सों में राज्य की प्रभुसत्ता को चुनौती दी। किंतु हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों की रणनीति, विकास योजनाओं और स्थानीय जागरूकता ने इसके प्रभाव को काफी हद तक सीमित कर दिया है। कई विद्वानों और नीति विशेषज्ञों ने इसके धीरे-धीरे समाप्त होने की संभावना जताई है। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर का मानना है कि नक्सलवाद तब तक जीवित रहेगा जब तक आदिवासियों को विकास के नाम पर विस्थापित किया जाता रहेगा। किंतु यदि "लोकतांत्रिक विकास" और न्यायपरक शासन लाया जाए, तो यह आंदोलन अपनी प्रासंगिकता खो देगा ।[32] अजॉय घोष मेमोरियल व्याख्यान में लेखक गौतमनायारण के अनुसार, माओवादी आंदोलन की रणनीतिक विफलताएं, विशेषतःजनता के बीच समर्थन की कमी और आंतरिक गुटबाज़ी, इसके पतन के संकेत हैं।[33] पूर्व पुलिस महानिदेशक बी.के. सिंह का विश्लेषण है कि "Clear, Hold and Develop" रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से अगले दशक में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो सकता है।[34] सामाजिक कार्यकर्ता अत्तियार ने 2020 में कहा था कि यदि स्थानीय युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ा जाए, तो नक्सलवाद में भर्ती लगभग रुक जाएगी।[35] रिपोर्ट के

अनुसार, केंद्र सरकार की 'समग्र रणनीति' (सुरक्षा + विकास) के तहत 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य वास्तविकता में बदल सकता है।[36] ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सीपीआई (माओवादी) के महासचिव बासवराजू सहित 27 उग्रवादी मारे गए। यह नक्सल आंदोलन की रीढ़ तोड़ने वाला निर्णायक क्षण माना गया।[37] सुकमा और बीजापुर में स्थानीय युवाओं के लिए स्थापित कौशल केंद्रों ने नक्सली भर्ती में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की ।[38] तेलंगाना मॉडल, जहाँ उग्रवादियों को आत्मसमर्पण कर पुनर्वास दिया गया, उसे अन्य राज्यों ने भी अपनाया है।[39] नक्सलवाद का पराभव केवल सैन्य सफलता से संभव नहीं है। यह तभी टिकाऊ होगा जब सामाजिक न्याय, शिक्षा, भूमि अधिकार और आदिवासी अस्मिता की रक्षा हो। विद्वानों की राय स्पष्ट है कि यह एक राजनीतिक-सामाजिक समस्या है, जिसका सुरक्षा-राजनीति-न्याय से संतुलित समाधान ही स्थायी होगा। आज भले ही माओवादी आंदोलन अपनी चरम अवस्था से गिरावट की ओर हो, किंतु जब तक मूलभूत असमानताएं बनी रहेंगी, इसकी चिंगारी बुझने में समय लगेगा।[40] सरकार की विकासोन्मुखी और समावेशी रणनीति ही इसका स्थायी अंत सुनिश्चित कर सकती है।

CM Sai in Delhi to brief PM Modi on anti-Maoist ops

TIMES NEWS NETWORK

Raipur: Day after a top Maoist commander was killed in Bijapur district of Chhattisgarh, chief minister Vishnu Deo Sai has rushed to New Delhi to brief Prime Minister Narendra Modi about the success in anti-Maoist operations front and the development of state.

"I am visiting New Delhi for two days. I will be meeting the Prime Minister and discuss the development of Chhattisgarh. I will also brief him about our fight against Naxalism and the successes we have had," CM Sai said just before boarding the flight.

Hailing the successful anti-Naxal operation, which neutralised Sudhakar, a Central Committee Member (CCM), the chief minister saluted the jawans for their bravery in carrying out such operations. "Operations are going on continuously, and we are achieving success," he said.

Sources indicate that the meeting will also involve a review of ongoing Central govt schemes in Chhattisgarh.

Another top Maoist killed in encounter

Raipur: In yet another big blow to the Left Wing Extremism (LWE), another senior Maoist rank cadre — Bhaskar, who carried Rs 45 lakh bounty — was neutralized on Friday in an encounter that broke out in the same area where Maoists central committee member Sudhakar alias Tentu Lakshmi Narasimha Chalam was gunned down on Thursday in the forests of Bijapur. The encounter was part of the same anti-Maoist operation underway since Wednesday being carried out by personnel from the state police's Special Task Force (STF), District Reserve Guard (DRG) and CoBRA. Intermittent firing between security forces and the Maoist ultras took place the whole day and after the guns fell silent, security forces recovered the body of 45-year-old Maoist Bhaskar, who carried a bounty of Rs 25 lakh in Chhattisgarh and Rs 20 lakh in Telangana. P2

निष्कर्ष :

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले क्षेत्र में नक्सलवाद पैर पसार चूका था। वर्तमान परिदृश्य में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमाई इलाके में नक्सल के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया गया। कुर्रेगुट्टालू और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे समन्वित प्रयास यह साबित करते हैं यदि यही नीति और समर्पण जारी रहा, तो "नक्सलमुक्त भारत" केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक साकार होती सच्चाई बन सकता है।

गरीब किसानों और जमींदारों के बीच भूमि के अधिकार के संघर्ष से प्रेरित नक्सलबाड़ी का आंदोलन समय के फेर में बदलते-बदलते कुछ इस हद तक हो गया की भारतवर्ष के आतंरिक सुरक्षा को तारतार करने लग गया। नक्सलबाड़ी की हिंसा कही न कही एक जनाक्रोश था लेकिन आगामी समय में इसकी उद्देशिका ही बदल गयी ; जो समय के साथ-साथ भयावह और लाल आतंक के रूप में प्रदर्शित है। नक्सल और सैन्य संघर्षो में दोनों ओर से गोलिया चल रही है और दोनों ओर जनहानि हो रही है। बहते लहू के रंगों

में ये अंतर कर पाना संभव नहीं है की नक्सल का लहू है या सैनिक का लहू है? मुख्यधारा के विपरीत चलने वाली धारा का लगभग ढलान अंत की ओर है ये समय के गर्भ में संचित है।

संदर्भ ग्रन्थ -

1. Chandra, B. (2008). *India Since Independence*. Penguin Books.
2. Hauser, W. (1992). *Rebels and the Raj: Naxalite Movement in India*. Oxford University Press.
3. Banerjee, S. (2006). *In the Wake of Naxalbari: A History of the Naxalite Movement in India*. Three Essays Collective.
4. Sundar, N. (2016). *The Burning Forest: India's War in Bastar*. Juggernaut Books.
5. Guha, R. (2011). *India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy*. Picador India.
6. Chandra, B. (2008). India Since Independence. Penguin Books.
7. Banerjee, S. (2006). In the Wake of Naxalbari: A History of the Naxalite Movement in India. Seagull Books.
8. Guha, R. (2011). India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy. Picador.
9. Sundar, N. (2016). The Burning Forest: India's War in Bastar. Juggernaut.
10. Hauser, W. (1992). The Naxalite Rebellion. Cornell University Press.
11. Raghavan, V. (2012). Naxalism: At the Crossroads. Kalpaz Publications.
12. Singh, P. (2007). Maoist Insurgency in India: Combating Left Wing Extremism. Rupa Publications.
13. Verma, A. (2010). Internal Security in India: Issues and Perspectives. Pointer Publishers.
14. Guha, R. (2011). India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy. Picador.
15. Banerjee, S. (2006). India's Simmering Revolution: The Naxalite Uprising. Zed Books.
16. Sundar, N. (2016). The Burning Forest: India's War in Bastar. Juggernaut Books.
17. Human Rights Watch. (2008). Being Neutral is Our Biggest Crime: Government, Vigilante, and Naxalite Abuses in India's Chhattisgarh State. https://www.hrw.org/report/2008/07/14/being-neutral-our-biggest-crime/government-vigilante-and-naxalite-abuses-indias
18. Raghavan, V. R. (2012). Internal Conflicts in India: A Review of Naxalite Insurgency. Vij Books India.
19. Guha, R. (2011). India after Gandhi: The History of the World's Largest Democracy. HarperCollins.
20. गृह मंत्रालय(2025). 'नक्सलमुक्त भारत' के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षाबलों ने नक्सलवाद के विरुद्ध अबतक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के कुर्रेगुट्टालू पहाड़ (KGH) पर 31 नक्सलियों को मार गिराया. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2128737

21. गृह मंत्रालय(2025). केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2130297

22. Banerjee, S. (2012). *Understanding Naxalism: Historical and Political Dimensions*. Economic and Political Weekly, 47(45), 14–17.

23. Shah, A. (2010). *In the Shadows of the State: Indigenous Politics, Environmentalism, and Insurgency in Jharkhand, India*. Duke University Press.

24. Mishra, R. (2009). *Maoist Insurgency and India's Internal Security*. Kalpaz Publications.

25. Chakrabarty, B., & Kujur, R. (2015). *Left-Wing Extremism in India*. Routledge.

26. Baviskar, A. (2007). *In the Belly of the River: Tribal Conflicts over Development in the Narmada Valley*. Oxford University Press.

27. Guha, R. (2013). *India after Gandhi: The History of the World's Largest Democracy*. HarperCollins.

28. Singh, U. K. (2011). *The State, Democracy and Anti-Terror Laws in India*. SAGE Publications.

29. Ekka, A., & Kujur, J. M. (2008). *Development-Induced Displacement and the Maoist Movement in India*. Indian Social Institute.

30. Verma, R. (2012). *The Naxalite Movement: A Case Study*. Indian Journal of Political Science, 73(1), 145–157.

31. Sundar, N. (2016). *The Burning Forest: India's War in Bastar*. Juggernaut Books.

32. Sundar, N. (2016). *The Burning Forest: India's War in Bastar*. Juggernaut Books.

33. Narayan, G. (2009). *Ajoy Ghosh Memorial Lecture: Understanding the Crisis of Left-Wing Extremism*. Indian Journal of Political Science, 70(4), 1127–1134.

34. Singh, B. K. (2013). *Countering Naxalism: A Strategy for India*. Journal of Defence Studies, 7(3), 21–35.

35. Attiyar, V. (2020). *Youth and Insurgency in Central India*. Economic & Political Weekly, 55(42), 55–60.

36. India Foundation. (2021). *Naxalism in India: Changing Nature of the Threat*. Retrieved from https://indiafoundation.in

37. Ministry of Home Affairs (MHA). (2024). *Press Release on Operation Black Forest*. https://mha.gov.in

38. UNDP. (2023). *Empowering Youth in Conflict Areas: The Chhattisgarh Model*. Retrieved from https://undp.org

39. Reddy, M. S. (2019). *Telangana's Surrender Policy: A Model for Reintegration*. South Asia Journal, 13(2), 42–47.

40. Menon, S. (2022). *Land Rights and Conflict in India*. Oxford University Press.